



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 9 जून, 2023

ज्येष्ठ 19, 1945 शक सम्वत्

प्रारूप-18

{नियम 20 का उपनियम (2)}

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा प्रारम्भिक अधिसूचना  
{अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत}

उत्तर प्रदेश सरकार

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।

अधिसूचना संख्या 3175-आठ-अ०जि०अ०/भू०अ०-गाजियाबाद

दिनांक : 9 जून, 2023

### अधिसूचना

प०आ०-401

1-भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय हैं कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद की सुनियोजित विकास योजना हेतु जनपद गाजियाबाद, तहसील गाजियाबाद परगना लोनी के ग्राम-पसौंड़ा की कुल 0.1351 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

2-राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गई है जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक 24 जून, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3-सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है:-

प्रस्तावित सुनियोजित विकास योजना में कुल 02 परिवार, 30 सदस्य हैं। परियोजना के चालू होने से मौजूदा परिस्थितियों में सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव हैं। यातायात से भीड़ की कमी, त्वरित सेवा, सुरक्षित यातायात, वायु प्रदूषण में कमी व रोजगार के अवसर परियोजना के विकास के परिणाम स्वरूप होना व कोई सांस्कृतिक/एतिहासिक स्मारक प्रभावित न होना। यह योजना सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति करती है इसलिए यह दिल्ली और गाजियाबाद के घनी आबादी के शहरों में यातायात की समस्याओं के समाधान व पारंपरिक वाहनों से उत्सर्जित होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में सुगम और किफायती यातायात प्रणाली है। इसलिए यह परियोजना सार्वजनिक उद्देश्यों को पूरा करती है।

4-भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार के विस्थापित होने की सम्भावना नहीं है।

उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-414/एक-13-2014-7(क)(8)/2014, लखनऊ, दिनांक 6 अगस्त, 2014 के द्वारा सम्बन्धित तहसील के यथा स्थिति सहायक कलेक्टर या उप कलेक्टर को उनकी अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर "पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक" नियुक्त किया गया है। इस शासनादेश के अनुक्रम में उपजिलाधिकारी गाजियाबाद को उनकी अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देती है:-

#### अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं०	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
गाजियाबाद	गाजियाबाद	लोनी	पसौंडा	854मि०	0.0040
गाजियाबाद	गाजियाबाद	लोनी	पसौंडा	855मि०	0.0050
गाजियाबाद	गाजियाबाद	लोनी	पसौंडा	1772मि०	0.0293
गाजियाबाद	गाजियाबाद	लोनी	पसौंडा	1773मि०	0.0388
गाजियाबाद	गाजियाबाद	लोनी	पसौंडा	1774मि०	0.0350
गाजियाबाद	गाजियाबाद	लोनी	पसौंडा	1775मि०	0.0230
				<b>योग</b>	<b>0.1351</b>

6-अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निदेश देती है।

7-अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8-अधिनियम की धारा 11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

**टिप्पणी :-** उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर गाजियाबाद के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,  
राकेश कुमार सिंह  
समुचित सरकार/कलेक्टर,  
गाजियाबाद।

FORM-18

[Sub rule (2) of Rule 20]

Preliminary Notification by Appropriate Government/Collector

[Under Sub-section (1) of section 11 of the Act]

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH  
Housing and Urban Planning Department

Notification no. 3175/8-ADM-LA-Ghaziabad

Dated, June 9, 2023

Under sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013. Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of 0-1351 Hectares of land is required in the Village Pasonda, Pargana Loni, Tehsil Ghaziabad, District Ghaziabad, is required for public purpose, namely Planed development Scheme through Ghaziabad Development Authority, Ghaziabad.

2. Social Impact Assessment Study was carried out by the State Social Impact Assessment agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated June 24, 2022.

3. The summary of the Social Impact Assessment Report as follows: -

There are total 02 families, 30 members in the proposed Planned Development Scheme. The commissioning of the project has positive environmental impact under the existing conditions. The development of the project will result in reduction of traffic congestion, faster service, safer traffic, reduction in air pollution and employment opportunities and no cultural/historical monuments will be affected. The scheme serves public purposes, therefore it is a convenient and economical transport system to solve traffic problems in the densely populated cities of Delhi and Ghaziabad and to control air pollution emitted by conventional vehicles. Hence the project serves public objectives.

4. There is no possibility of displacement of any family due to land acquisition.

"U.P. Government Order number-414/One-13-2014-7(a)(8)-2014, Lucknow dated August 06, 2014 to the Assistant Collector or Deputy Collector, as the case may be, within their respective territorial jurisdiction the concerned Tehsil" has been appointed as "Rehabilitation and Resettlement Administrator".

In pursuance of the Government Order, the Deputy Collector, Ghaziabad is appointed as the Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the affected families within their respective territorial jurisdiction.

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the schedule below is needed for public purpose.

#### SCHEULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be Acquired (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Ghaziabad	Ghaziabad	Loni	Pasonda	854 m	0-0040
Ghaziabad	Ghaziabad	Loni	Pasonda	855 m	0-0050
Ghaziabad	Ghaziabad	Loni	Pasonda	1772 m	0-0293
Ghaziabad	Ghaziabad	Loni	Pasonda	1773 m	0-0388
Ghaziabad	Ghaziabad	Loni	Pasonda	1774 m	0-0350
Ghaziabad	Ghaziabad	Loni	Pasonda	1775 m	0-0230
				<b>Total</b>	<b>0-1351</b>

6. The Governor is also pleased to authorize the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub-soil into the sub-soil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under Section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the collector.

8. Under Section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the collector.

NOTE :- A plan of the land may be inspected in the office of the collector Ghaziabad for the purpose of Acquisition.

By order,  
RAKESH KUMAR SINGH,  
Appropriate Government/Collector,  
Ghaziabad.